

11 मई 2024 : समाचार विश्लेषण**A. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:**

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

B. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:**अंतर्राष्ट्रीय संबंध:**

- भारत संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की दावेदारी का समर्थन करता है:
- 18 महीने बाद चीन ने भारत में भेजा राजदूत:

C. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

D. सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 4 से संबंधित:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

E. संपादकीय:**भूगोल:**

- मीठे पानी की खोज, संभावित नए सोने की खोज:

F. प्रीलिम्स तथ्य:

1. मार्च में औद्योगिक उत्पादन घटकर 4.9% रह गया:
2. फोल्ड्स और फॉल्ट्स:

G. महत्वपूर्ण तथ्य:

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

H. UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:**I. UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:****सामान्य अध्ययन प्रश्न 2 से संबंधित:**

भारत संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की दावेदारी का समर्थन करता है:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

विषय: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्हूं और समझौते

मुख्य परीक्षा : भारत-फिलिस्तीन संबंध

प्रसंग:

- संयुक्त राष्ट्र में पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की बोली के पक्ष में भारत का हालिया वोट मौजूदा फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक कदम है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के आपातकालीन विशेष सत्र में प्रस्तुत प्रस्ताव को व्यापक समर्थन मिला, जिसने इस मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रुख को उजागर किया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा संकल्प:

- संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के समर्थन में एक प्रस्ताव को अपनाना।
- 143 अन्य देशों के साथ भारत ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया।

- प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की योग्यता को मान्यता देता है और सुरक्षा परिषद द्वारा अनुकूल पुनर्विचार की सिफारिश करता है।

फिलिस्तीन के लिए भारत का ऐतिहासिक समर्थन:

- फिलिस्तीनी मुददे को भारत का लंबे समय से समर्थन।
- 1974 में फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलिस्तीन मुक्ति संगठन (पीएलओ) की मान्यता।
- 1988 में फिलिस्तीन राज्य की मान्यता।
- 1996 में गाजा में फिलिस्तीन प्राधिकरण के लिए भारत के प्रतिनिधि कार्यालय की स्थापना, बाद में 2003 में रामल्ला में स्थानांतरित कर दिया गया।

फिलिस्तीन के लिए अधिकार और विशेषाधिकार:

- संकल्प के अनुबंध में फिलिस्तीन के लिए अतिरिक्त अधिकारों और विशेषाधिकारों की रूपरेखा दी गई है।
- महासभा के 79वें सत्र से प्रभावी।
- इसमें सदस्य देशों के बीच बैठना, समूहों की ओर से बयान देना, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में भागीदारी और अधिकारियों के रूप में चुनाव के लिए पात्रता शामिल है।

फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति:

- फिलिस्तीन को वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त है।
- संयुक्त राष्ट्र के अंगों के लिए मतदान के अधिकार और उम्मीदवारी पर सीमाएँ।

महत्व:

- भारत का वोट फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं का समर्थन करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
- अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और संघर्ष समाधान प्रयासों में भारत की सक्रिय भागीदारी को दर्शाता है।
- जटिल भू-राजनीतिक मुद्दों के समाधान में बहुपक्षवाद और कूटनीतिक संवाद के महत्व पर प्रकाश डाला गया।

समाधान:

- फिलिस्तीन और इज़राइल के बीच बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए राजनयिक प्रयास जारी रखे।
- दो-राज्य समाधान और क्षेत्र में स्थायी शांति प्राप्त करने के उद्देश्य से पहल के लिए समर्थन।
- फिलिस्तीन में प्रभावित आबादी की पीड़ा को कम करने के लिए मानवीय सहायता और विकास सहायता।

सारांश:

- संयुक्त राष्ट्र की पूर्ण सदस्यता के लिए फिलिस्तीन की बोली के लिए भारत का समर्थन फिलिस्तीनी-इजरायल संघर्ष पर उसके सैद्धांतिक रुख और न्याय, समानता और अंतरराष्ट्रीय

कानून के सिद्धांतों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आगे बढ़ते हुए, संघर्ष का उचित और स्थायी समाधान प्राप्त करने, मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए ठोस राजनीतिक प्रयास और रचनात्मक बातचीत आवश्यक हैं।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से संबंधित:

18 महीने बाद चीन ने भारत में भेजा राजदूत:

अंतर्राष्ट्रीय संबंध:

विषय: भारत से जुड़े और/या भारत के हितों को प्रभावित करने वाले द्विविक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सम्बन्धों समझौते

मुख्य परीक्षा : भारत-चीन संबंध

प्रसंग:

- चीन द्वारा 18 महीने के अंतराल के बाद भारत में राजदूत के रूप में जू फेइहोंग की नियुक्ति दोनों देशों के बीच द्विविक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। श्री जू का आगमन सीमा पर तनाव और भू-राजनीतिक जटिलताओं के कारण तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है।

जू फेइहोंग की नियुक्ति:

- चीनी राजनीतिक जू फेइहोंग ने भारत में 17वें राजदूत के रूप में पदभार ग्रहण किया।
- स्थिर भारत-चीन संबंधों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में आदान-प्रदान और सहयोग बहाल करने को प्राथमिकता देता है।
- प्रतिस्पर्धा पर सहयोग और खतरों पर विकास के अवसरों पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के आपसी समझौते पर जोर दिया गया।

तनावपूर्ण संबंधों की पृष्ठभूमि:

- अप्रैल 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर तनाव।
- जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में दोनों पक्षों के लोग हताहत हुए।
- 18 महीने तक भारत में चीन के राजदूत की अनुपस्थिति से राजनीतिक तनाव बढ़ जाता है।

राजनीतिक आउटरीच:

- श्री जू आशावाद व्यक्त करते हैं और भारत सरकार और विभिन्न क्षेत्रों से समर्थन चाहते हैं।
- महत्वपूर्ण पड़ोसियों और उभरते बाजारों के रूप में भारत-चीन संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालता है।
- वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों पर निकट संचार और समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया।

हालिया वक्तव्य और घटनाक्रम:

- भारत और चीन दोनों ने हालिया बयानों में बेहतर संबंधों की इच्छा व्यक्त की है।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीमा संबंधी मुद्दों को सुलझाने और शांति बहाल करने के लिए रचनात्मक जु़़ाव का आह्वान।
- दोनों पक्षों ने राजनीतिक और सैन्य स्तरों पर सकारात्मक द्विविक्षीय जु़़ाव के महत्व पर जोर दिया।

महत्व:

- जू फेइहोंग की नियुक्ति चीन की ओर से भारत के साथ जुड़ने के लिए नए सिरे से कूटनीतिक प्रयास का संकेत देती है।
- क्षेत्र में तनाव कम करने और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय बातचीत और सहयोग की संभावना।
- लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को सुलझाने और विश्वास कायम करने में रचनात्मक जुड़ाव और संवाद का महत्व।

समाधान:

- बातचीत और संघर्ष समाधान के लिए राजनयिक चैनलों को प्राथमिकता दें।
- सीमा प्रबंधन के लिए विश्वास-निर्माण उपायों और रूपरेखाओं का अन्वेषण करें।
- आपसी समझ को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच आदान-प्रदान और सांस्कृतिक कूटनीति में संलग्न रहें।

सारांश:

- भारत में चीन के राजदूत के रूप में जू फीहोंग की नियुक्ति दोनों देशों के लिए अपने राजनयिक जुड़ाव को फिर से मजबूत करने और लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों को संबोधित करने का अवसर प्रदान करती है। चूंकि भारत और चीन जटिल भू-राजनीतिक गतिशीलता से गुजर रहे हैं, इसलिए क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए निरंतर बातचीत और सहयोग आवश्यक है।

संपादकीय-द हिन्दू**संपादकीय:**

मीठे पानी की खोज, संभावित नए सोने की खोज:

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 से संबंधित:

भूगोल:

विषय: भारत और विश्व का भौतिक भूगोल।

मुख्य परीक्षा: समुद्र तल के नीचे मीठे पानी के जलाशयों का महत्व।

संदर्भ:

- समुद्र तल के नीचे मीठे पानी के भंडारों की खोज ने मीठे पानी के संसाधनों की खोज में एक नई रुचि जगाई है। सतह पर मीठे पानी का केवल एक छोटा सा अंश उपलब्ध होने के कारण, बढ़ते मीठे पानी के संकट को दूर करने के लिए पानी के भीतर मीठे पानी के स्रोतों की खोज और दोहन महत्वपूर्ण हो जाता है।

सांख्यिकी और वैशिक संदर्भ:

- पृथ्वी की कुल जल मात्रा: 1.386 बिलियन किमी³

- वितरण: 97.5% खारा पानी, 2.5% मीठा पानी
- तरल मीठे पानी की उपलब्धता: सतह पर केवल 0.3%
- मीठे पानी का अधिकांश भाग: भूमिगत, समुद्र तल के नीचे सहित

कानूनी ढांचा: UNCLOS और जिनेवा कन्वेशन:

- UNCLOS (समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेशन) समुद्री क्षेत्रों और संसाधनों को नियंत्रित करता है।
- समुद्र के कानून पर जिनेवा कन्वेशन, 1958, भी महत्वपूर्ण है।
- UNCLOS का अनुच्छेद 311 राज्यों की पार्टियों के लिए जिनेवा कन्वेशन पर हावी है।
- अमेरिका जैसे कुछ देशों ने जिनेवा कन्वेशन के हस्ताक्षरकर्ता हैं, लेकिन UNCLOS के नहीं, जिससे समुद्री क्षेत्रों की उनकी मान्यता प्रभावित हो रही है।

पानी के भीतर मीठे पानी की खोज और दोहन:

- UNCLOS राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे "क्षेत्र" से खनिज संसाधनों की खोज और दोहन की अनुमति देता है।
- UNCLOS के तहत "संसाधन" और "खनिज" की परिभाषा: ठोस, तरल या गैसीय खनिजों पर ध्यान केंद्रित करना, मीठे पानी के समावेशन के बारे में सवाल उठाना।
- अंतर्राष्ट्रीय सीबेड प्राधिकरण "क्षेत्र" में गतिविधियों को नियंत्रित करता है।
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे मीठे पानी के निष्कर्षण के लिए विशिष्ट कानून का अभाव चुनौतियाँ प्रस्तुत करता है।

महत्व और भविष्य के निहितार्थ:

- भविष्य के संघर्षों और भू-राजनीतिक तनावों के लिए एक चालक के रूप में पानी की कमी।
- पानी के नीचे मीठे पानी के जलाशय मीठे पानी की कमी के संभावित समाधान का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे मीठे पानी की खोज और निष्कर्षण को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विधायी ढांचे की आवश्यकता।

भावी कदम:

- राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे मीठे पानी की खोज और निष्कर्षण के लिए स्पष्ट कानूनी ढांचे और नियम स्थापित करना।
- पानी के भीतर मीठे पानी के संसाधनों को नियंत्रित करने के लिए राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग बढ़ाना।
- टिकाऊ निष्कर्षण विधियों और पर्यावरणीय प्रभाव शमन के लिए अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में निवेश करना।

सारांश:

- समुद्र के नीचे मीठे पानी के भंडार की खोज वैश्विक मीठे पानी के संकट का एक आशाजनक समाधान प्रस्तुत करती है। हालाँकि, इन संसाधनों तक स्थायी और न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कानूनी अस्पष्टताओं और शासन संबंधी चुनौतियों का समाधान किया जाना चाहिए। मानवता के लाभ के लिए पानी के भीतर मीठे पानी की क्षमता का दोहन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सक्रिय विधायी प्रयास आवश्यक हैं।

प्रीलिम्स तथ्य:

1. मार्च में औद्योगिक उत्पादन घटकर 4.9% रह गया:

प्रसंग: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की औद्योगिक उत्पादन वृद्धि फरवरी में 5.6% से घटकर मार्च में 4.9% हो गई। मंदी का कारण पिछले वर्ष के आधार प्रभाव और विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग प्रदर्शन हैं।

क्षेत्रवार प्रदर्शन:

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में 77.6% हिस्सेदारी रखने वाला विनिर्माण, मार्च में पांच महीने के उच्चतम स्तर 5.2% पर पहुंच गया।
- खनन उत्पादन में 19 महीने की सबसे कम 1.2% की वृद्धि देखी गई, जबकि बिजली उत्पादन में 8.6% की वृद्धि हुई।
- बुनियादी ढांचे और निर्माण वस्तुओं में मार्च में 6.9% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पूँजीगत वस्तुओं में 6.1% की वृद्धि देखी गई।

वर्ष-दर-वर्ष तुलना:

- 2023-24 में कुल औद्योगिक उत्पादन में 5.8% की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की 5.2% वृद्धि से थोड़ा अधिक है।
- विनिर्माण उत्पादन में 2022-23 में 4.7% से 5.5% की वृद्धि हुई, जबकि खनन उत्पादन में 7.5% की वृद्धि हुई।
- उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और गैर-टिकाऊ वस्तुओं में पिछले वर्ष की तुलना में मामूली वृद्धि दर्ज की गई।

चुनौतियाँ और चिंताएँ:

- मार्च में 23 प्रमुख विनिर्माण क्षेत्रों में से सात में गिरावट दर्ज की गई।
- मिश्रित उपभोग परिवर्श्य में शहरी मांग में लचीलापन दिख रहा है जबकि ग्रामीण मांग पीछे है।
- आधार प्रभाव के कारण अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि दर घटकर 3% से 4% रहने की उम्मीद।

आउटलुक और उम्मीदें:

- उपभोग पैटर्न और ग्रामीण मांग की निगरानी पर निरंतर ध्यान।
- पिछले वर्ष के आधार प्रभावों के कारण अप्रैल में औद्योगिक उत्पादन वृद्धि में मंदी की आशंका है।
- औद्योगिक उत्पादन में व्यापक-आधारित और टिकाऊ सुधार हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता।

2. फोल्ड्स और फॉल्ट्स:

प्रसंग: डीपमाइंड द्वारा विकसित एक एआई उपकरण अल्फाफोल्ड ने संरचनात्मक जीव विज्ञान में क्रांति लाते हुए उच्च सटीकता के साथ प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करने की अपनी क्षमता के लिए ध्यान आकर्षित किया है। अल्फाफोल्ड 3 की हालिया रिलीज डीएनए, आरएनए, लिंगेंड और संशोधनों के मॉडलिंग सहित और प्रगति का वादा करती है। हालाँकि, इसके आंतरिक तंत्र तक सीमित पहुंच और दवा की खोज के संभावित प्रभावों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं।

प्रोटीन फोल्डिंग समस्या:

- प्रोटीन अपने सामान्य कार्य के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट आकृतियों में बदल जाते हैं।
- अल्फाफोल्ड प्रोटीन संरचनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की दीर्घकालिक चुनौती का समाधान करता है।
- महत्व: प्रोटीन फोल्डिंग को समझना रोग तंत्र और दवा की खोज को समझने में सहायता करता है।

अल्फाफोल्ड का विकास:

- 2018 में डीपमाइंड द्वारा अल्फाफोल्ड का विकास, उसके बाद अल्फाफोल्ड 2 का विकास।
- अल्फाफोल्ड 3 की उन्नत क्षमताएं, जिनमें लगभग 80% सटीकता के साथ आकृतियों की भविष्यवाणी करना शामिल है।
- पारंपरिक सूक्ष्मदर्शी तकनीकों की तुलना में तीव्र संरचनात्मक व्याख्या।

चुनौतियाँ और सीमाएँ:

- प्रोटीन फोल्डिंग के पीछे के तर्क को समझाने में अल्फाफोल्ड की असमर्थता एक चुनौती बनी हुई है।
- दवा की खोज और नैदानिक परीक्षणों पर इसके प्रभाव के संबंध में अनिश्चितता।
- अल्फाफोल्ड के आंतरिक तंत्र तक सीमित पहुंच और वैज्ञानिक नवाचार के संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं।

पहुंच और पारदर्शिता:

- अल्फाफोल्ड 3 के मुफ्त उपयोग पर वर्तमान सीमाएं और इसके आंतरिक कामकाज में पारदर्शिता की कमी।
- प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी में जांच और आगे नवाचार की सुविधा के लिए सार्वजनिक पहुंच का महत्व।
- प्रतिबंधात्मक भुगतान के बिना व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक राजस्व मॉडल की आवश्यकता।

महत्वपूर्ण तथ्यः

आज इससे संबंधित कुछ नहीं है।

UPSC प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्नः**प्रश्न 1. निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः**

1. 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र से फिलिस्तीन को सदस्य देशों के बीच बैठने और संयुक्त राष्ट्र की गतिविधियों में पूर्ण रूप से भाग लेने जैसे अधिकार प्राप्त होंगे।
2. वर्तमान में, एक पर्यवेक्षक राज्य के रूप में, फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र के भीतर पदों के लिए मतदान या नामांकन नहीं कर सकता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः **c**

व्याख्या : ये दोनों कथन सही हैं।

प्रश्न 2. समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः

1. UNCLOS महासागरों के उपयोग के संबंध में राष्ट्रों के अधिकारों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है।
2. UNCLOS के तहत, राष्ट्रों को तटरेखा के साथ 1000 मील क्षेत्र के भीतर समुद्री संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने का विशेष अधिकार दिया जाता है।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन गलत है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तरः **b**

व्याख्या : UNCLOS के तहत, राष्ट्रों को तटरेखा के साथ 200 मील क्षेत्र के भीतर समुद्री संसाधनों का पता लगाने और उनका दोहन करने का विशेष अधिकार दिया जाता है।

प्रश्न 3. कोर सेक्टर उद्योगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंः

1. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का भार 50% से अधिक है।

2. कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली आठ प्रमुख क्षेत्र के उद्योग बनाते हैं।

उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: b

व्याख्या : इनमें औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में शामिल वस्तुओं का लगभग 40.27% हिस्सा शामिल है।

प्रश्न 4. अक्सर खबरों में नजर आने वाले 'अल्फाफोल्ड' और 'अल्फाफोल्ड 2' हैं:

- (a) अध्ययन दल जो एड टेक प्लेटफार्म से मुफ्त अध्ययन सामग्री प्रदान करके शिक्षा का लोकतंत्रीकरण करते हैं
- (b) भारत द्वारा विकसित मानवयुक्त पनडुब्बियां
- (c) पर्वत परतों और घाटी परतों का अध्ययन करने के लिए सिस्टम
- (d) एआई सिस्टम जो प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करते हैं

उत्तर: d

व्याख्या : डीपमाइंड ने 2018 में अल्फाफोल्ड और 2020 में अल्फाफोल्ड 2 विकसित किया, एआई सिस्टम जो प्रोटीन संरचनाओं की भविष्यवाणी करते हैं, प्रोटीन कॉन्फिगरेशन की हमारी समझ को बढ़ाते हैं।

UPSC मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न:

प्रश्न 1. मध्य पूर्व में अपने व्यापक रणनीतिक हितों के आलोक में फिलिस्तीन के प्रति भारत की विदेश नीति का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। चर्चा करें कि भारत का रुख क्षेत्र की अन्य प्रमुख शक्तियों के साथ उसके संबंधों को कैसे प्रभावित कर सकता है। (250 शब्द, 15 अंक) (सामान्य अध्ययन - II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध) (Critically analyze India's foreign policy towards Palestine in light of its broader strategic interests in the Middle East. Discuss how India's stance could influence its relations with other major powers in the region. (250 Words, 15 Marks) (General Studies - II, International Relations))

प्रश्न 2. समुद्र के भीतर मीठे पानी के संसाधनों की खोज और दोहन में अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन, 1982 (UNCLOS) की भूमिका की आलोचनात्मक समीक्षा करें। (150 शब्द, 10 अंक) (सामान्य अध्ययन - II, अंतर्राष्ट्रीय संबंध) (Critically examine the role of international law, particularly the United Nations Law of the Sea Convention, 1982 (UNCLOS), in the exploration and exploitation of subsea freshwater resources. (150 Words, 10 Marks) (General Studies - II, International Relations))

(नोट: मुख्य परीक्षा के अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों पर क्लिक कर के आप अपने उत्तर BYJU'S की वेब साइट पर अपलोड कर सकते हैं।)

